

प्रेमक,

श्रीमती इन्दिरा आरोंप,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
मैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

देहरादून : दिनांक : 15 नवम्बर, 2006

विषय: मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय परिसर के ओक पार्क में मा० न्यायाधीश आवास(कॉटेज संख्या 17-18) के लॉन में रेलिंग लगाने व टेरिस के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2635/IIIIC/Admin.B/Const/2006, दिनांक 11.10.2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय परिसर के ओक पार्क में मा० न्यायाधीश आवास(कॉटेज संख्या 17-18) के लॉन में रेलिंग लगाने व टेरिस के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में रु० 1,74,000/- के आगणन के विरुद्ध टी०ए०सी० द्वारा संस्तुत रु० 1,67,000/- (रुपये एक लाख सरसठ हजार मात्र) को लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रुपये 1,67,000/- (रुपये एक लाख सरसठ हजार मात्र) की धनराशि के व्यय किये जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- (1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को, जो दरे शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।
- (2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।
- (3) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय । स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।
- (4) एक मुश्त प्राविधान का कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
- (5) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।
- (6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भूतली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर ली जाय । निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण रिपोर्टों के अनुरूप कार्य किया जाय ।
- (7) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।
- (8) निर्माण सामग्री का प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपर्युक्त पायी जानी वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय ।

- (9) न्याय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पचेज रूलस, मितव्ययता के सम्वन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अभिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।
- (10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।
- (11) निर्माण कार्य कराते समय अथवा आगणन गदित करत समय मुख्य सचिव, उत्तरांचल के शासनादेश संख्या 2047/XVI/219(2006), 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
- 2- इस सम्वन्ध में होने वाला न्याय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 को आय-व्ययक की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "2014 न्याय प्रशासन-00-आयोजन-102-उच्च न्यायालय-03-उच्च न्यायालय-00-25-लघु निर्माण कार्य" के तर्फे डाला जायेगा ।
- 3- यह आदेश वित्त अनुभाग 5 के अशासकीय संख्या-658/XXVII(5)/2006, दिनांक 7.11.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भावनीया

(इन्दिरा आशीष)
सचिव ।

संख्या-39-दो(2)/XXXVI(1)/2006-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारों), औद्योगिक बिल्डिंग, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
4. मुख्य अभियन्ता, स्त-1 लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
5. अभिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल ।
6. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तरांचल शासन ।
7. एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।